- 19th Year
- Issue: 218
- 12.12.2025 (FRIDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

वंदे मातरम पर बहस में उछाला गया नेहरू का नाम, राज्यसभा में भिड़े खरगे-नड्डा, मचा घमासान

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): जेपी नड्डा द्वारा वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछा कि ज़्या चर्चा का विषय वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है या फिर चर्चा का मुज़्य विषय जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर नड्डा के भाषण के दौरान हस्तक्षेप किया और नेहरू पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि यह बहस वंदे मातरम को लेकर है या पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह विकृत है और सच नहीं है। यह सवाल दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस में बदल गया, जब नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत की संस्कृति से समझौता किया है।

राज्यसभा में सदन के नेता ने कहा कि मैं सिर्फ वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। अगर जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगतीं, तो मैं ज़्या कर सकता हूं? समस्या यह है कि शुरू से ही आप लोगों ने भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से समझौता किया है... दुर्गा, सरस्वती, भारत माता और शक्ति इस देश के सभी लोगों के लिए हैं, और सभी को उनमें आस्था है।

इन टिप्पणियों के कारण राज्यसभा में हंगामा मच गया और स्थिति को शांत करने के लिए अध्यक्ष उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को हस्तक्षेप करना पड़ा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस का समापन करते हुए जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि को धूमिल नहीं करना चाहती और उसका एकमात्र उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को सही करना है।

उन्होंने कहा, वंदे मातरम को वह सज़्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे... उस समय सज़ा में रहे लोग (सरकार) इस स्थिति के लिए जिज़्मेदार थे।

नड्डा ने कहा कि पहले तो आपने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के श्लोक हटा दिए। जून 1947 में आपने भारत को खंडित स्वतंत्रता दी और जिन्ना के सपनों को साकार किया। उसके बाद आपने पाकिस्तान की गुरिल्ला सेनाओं के सामने पीओके समर्पित कर दिया, खंडित कश्मीर पर कज़्जा कर लिया और फिर अनुच्छेद 370 लागू कर दिया... देश समझौतों से नहीं चलता - यही हमारी विचारधारा है। यह इतिहास की सच्चाइयों और अटूट राष्ट्रवाद की भावनाओं को ध्यान में रखकर चलता है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रवाद से जुड़ा गीत है। इसे वही स्थान मिलना चाहिए जो हमने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को दिया है।

साथी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना साझा कर्तव्य है, केवल सरकारों की जिमेदारी नहीं-राष्ट्रपति

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आह्वान किया कि मानवाधिकारों की रक्षा करना केवल सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) या ऐसे अन्य संस्थानों की ही जिज़्मेदारी नहीं है, बल्कि साथी नागरिकों के अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा करना एक ''साझा कर्तव्य'' है।

मानवाधिकार दिवस के मौके पर यहां एनएचआरसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये ''हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार अविभाज्य हैं और वे एक न्यायपूर्ण, समान और दयालु समाज की आधारशिला हैं। इस अवसर पर एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृज़्त) वी. रामासुब्रमण्यन और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा भी मंच पर उपस्थित थे। वर्ष 1950 से हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, ''आज मैं प्रत्येक नागरिक से यह समझने का आह्वान करती हूं कि मानवाधिकार केवल सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नागरिक समाज संगठनों और ऐसे अन्य संस्थानों की जिज़्मेदारी नहीं हैं। अपने साथी नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना हम सबका साझा कर्तव्य है। एक करुणामय और जिज़्मेदार समाज के सदस्य के रूप में यह हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा, ''आइए हम 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें, जो समग्र विकास और सामाजिक न्याय का आदर्श मिश्रण प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की मानवाधिकार सिद्धांतों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिल रही है, इसका प्रमाण भारत का सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तीन साल के कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना जाना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मानवाधिकार सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और उनमें ''बिना किसी डर के जीने का अधिकार, बिना किसी बाधा के सीखने का अधिकार, बिना शोषण के काम करने का अधिकार'' शामिल है।

निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- अमित शाह ने लोस में उनकी दलीलों को धोया

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का बचाव किया और विपक्ष पर निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया। दुबे की यह टिप्पणी शाह द्वारा चुनावी प्रक्रिया से लेकर शासन में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका तक के मुद्दों पर विपक्ष के नेता के भाषण का विस्तृत खंडन करने के एक दिन बाद आई है।

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए दुबे ने कहा कि अमित शाह ने अपने भाषण में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए हर मुद्दे का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। उन्होंने दावा किया, भारत के विभाजन के बाद, शहीदों की चिता पर, कांग्रेस पार्टी ने सज़ा का आनंद लिया, और सज़ा का आनंद लेने वाले परिवार के लोग देश, दुनिया और शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानते।

उन्होंने कांग्रेस के भीतर वंशवादी राजनीति की भाजपा की पुरानी आलोचना को दोहराया। दुबे ने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में तैयारी और गहराई का अभाव था, जिसके चलते गृह मंत्री के लिए उनके तर्कों का बिंदुवार खंडन करना आसान हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के आए थे; उनके भाषण के तीन मुज़्य बिंदुओं को गृह मंत्री ने बड़ी कुशलता से वॉशिंग मशीन में धो दिया, इसलिए न तो जनता राहुल गांधी के शज़्दों को गंभीरता से लेती है और न ही देश उन्हें गंभीरता से लेता है।

अमित शाह के लोकसभा में दिए गए दमदार भाषण के बाद से राजनीतिक तनाव चरम पर है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दबाने और ऐतिहासिक कथाओं को विकृत करने का आरोप लगाया था।

मोदी और उनकी पार्टी ने नहीं पढ़ी राष्ट्रगान पर लिखी महत्वपूर्ण किताबें-जयराम रमेश

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को लोकसभा में चल रही वंदे मातरम बहस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनके साथियों ने राष्ट्रगान की सच्ची भावना पर लिखी गई दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें भी नहीं पढ़ी हैं। ये पुस्तकें रुद्रंगशु मुखर्जी द्वारा लिखित %सॉन्ग ऑफ इंडिया- ए स्टडी ऑफ नेशनल एंथम और सज़्यसाची भट्टाचार्य द्वारा लिखित वंदे मातरम- द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग हैं।जयराम रमेश ने तीखे शज़्दों में कहा कि ये पुस्तकें दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा लिखी गई हैं।

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं से यह उज़्मीद करना अतिशयोक्ति है, जबकि वे जनता के सामने अपने झूठ के लिए बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा और राज्यसभा में तीन दिनों तक वंदे मातरम पर बहस हुई। कुछ भाषणों में राष्ट्रगान का ज़िक्र भी हुआ... यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और उनके पूरे दल ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत पर लिखी गई दो प्रामाणिक और महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं - जो भारत के दो सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों द्वारा सही मायने में लिखी गई हैं। यह उज़्मीद करना अतिशयोक्ति है कि झूठ के लिए बुरी तरह लताड़ने और बेनकाब होने के बाद भी वे ऐसा करेंगे। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना की भूमिका पर प्रकाश डाला, वहीं भाजपा और विपक्ष के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए।

नज़्सलवाद पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र, हमने इस समस्या को जड़ से मिटा दिया-मोहन यादव

भोपाल ११/१२ (संवाददाता): मध्यप्रदेश के मुज़्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस ने नज़्सलवाद को लेकर दोहरा रवैया अपनाया जबकि भारतीय जनता पार्टी पार्टी (भाजपा) की सरकार ने इसे जड़ से मिटा दिया है। यादव ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ''राज्य में कांग्रेस के (पूर्ववर्ती) शासनकाल में नज़्सलवाद बहुत बड़ी समस्या थी। हमने इस समस्या को जड़ से मिटा दिया है। सूबे के मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले नज़्सलियों से तकरीबन मुक्त हो चुके हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान नज़्सलियों ने एक मंत्री की हत्या कर दी थी। यादव ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर कहा,''नज़्सलवाद की समस्या की मूल जड़ सूबे के तत्कालीन मुज़्यमंत्री थे जो आज भी (नज़्सली कमांडर) माड़वी हिड़मा के मारे जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। यह रवैया कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताता है।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने की राजनीति में यकीन रखती है और इस पार्टी की पिछली सरकारों ने नज़्सलवाद जैसी समस्याओं को जिंदा रखा।

यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्यप्रदेश के 19वें मुज़्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्होंने अपनी सरकार की पिछले दो साल की उपलज़्धियां गिनाते हुए कहा कि इस अवधि में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं।

मुज़्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की तादाद दोगुनी हो गई है और औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत को पार कर गई है। यादव ने कहा कि उनकी सरकार मध्यप्रदेश को देश का सबसे ज़्यादा विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है।

संसद में ई-सिगरेट पर बवाल! अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर लगाया आरोप

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): गुरुवार को लोकसभा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य सदन के अंदर ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह न केवल संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। अध्यक्ष ओम बिरला ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अनुमति कभी नहीं दी गई थी और कहा कि यदि लिखित शिकायत दर्ज की जाती है और आरोप की पुष्टि होती है तो वे कड़ी कार्रवाई करेंगे।यह मामला प्रश्नकाल के दौरान तब उठा जब ठाकुर ने उठकर सदन के नियमों के बार-बार उल्लंघन का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पूरा सदन इस मुद्दे से अवगत हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महोदय, मेरा सदन से एक प्रश्न है। महोदय, पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज़्या आपने सदन में इसकी अनुमति दी है?

अध्यक्ष ने उज़र दिया, नहीं, कोई भी इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। ठाकुर ने कहा कि महोदय, ज़्या आपने इसकी जाँच की है? टीएमसी के कुछ सांसद इसका सेवन कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की माँगों को स्वीकार करते हुए, बिरला ने दोहराया कि आचार संहिता सभी सांसदों पर समान रूप से लागू होती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी औपचारिक शिकायत की गंभीरता से जाँच की जाएगी। उन्होंने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का भी आग्रह किया। ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी सांसदों से संविधान के नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध करता हूँ।

लूथरा ब्रदर्स ने भारत लौटकर जांच में सहयोग का भरोसा दिया

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): गोवा के अर्पोरा में स्थित बिर्च बाय रोमेओ लेन नाइटज़्लब में 6 दिसंबर की रात लगी आग के मामले में लूथरा ब्रदर्स ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जांच में सहयोग करने का भरोसा दिया है। बता दें कि इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद ज़्लब संचालक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या से जुड़े आरोप दर्ज किए गए हैं।

गौरतलब है कि दोनों भाई देश छोड़कर थाईलैंड चले गए थे, जिसके चलते उन पर कानूनी प्रक्रिया से बचने के आरोप लगाए गए। हालांकि, उनकी कानूनी टीम ने दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है और वे कानून से भागने वालों में शामिल नहीं हैं। मौजूद जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर के नेतृत्व वाली लीगल टीम ने उन्हें सलाह दी थी कि वे भारत लौटकर पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के सामने पेश हों, जिसके बाद दोनों ने बयान जारी कर कहा कि वे 11 दिसंबर को देश लौटेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे हैं। बयान में कहा गया है कि वे कानून का सज़्मान करने वाले नागरिक हैं और उन पर लगाए गए आरोप कि वे जांच से बच रहे हैं, पूरी तरह भ्रामक हैं। उनके अनुसार, देश लौटने का निर्णय किसी कानूनी रणनीति से प्रभावित नहीं है और वे न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा रखते हैं।इस बीच, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर थाईलैंड में दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और उनका प्रत्यर्पण शुरू हो चुका है। बता दें कि भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से प्रत्यर्पण संधि लागू है, जिसके तहत यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इंटरपोल ने भी उन पर ज़्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद तलाशी तेज हुई हैं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों भाई आग लगने के महज डेढ़ घंटे के भीतर ही ज़्लाइट टिकट बुक कर चुके थे और सुबह 5:30 बजे फुकेत के लिए रवाना हो गए थे, जिससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि, उनकी तरफ से दायर ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल याचिका में कहा गया है कि वे अज़्सर काम के सिलसिले में यात्रा करते रहते हैं और 6 दिसंबर को भी वे व्यावसायिक मीटिंग के लिए थाईलैंड गए थे। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि हादसे के वक्त किसी बाहरी परफॉर्मर के उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा था और ज़्लब प्रबंधन ने कोई ज्वलनशील सामग्री नहीं रखी थी। याचिका में दर्ज एफआईआर की धाराओं 105, 125 और 287 को लागू करने पर भी सवाल उठाए गए हैं, साथ ही कहा गया है कि वे जांच में सहयोग करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अदालत द्वारा लगाए गए किसी भी शर्त को स्वीकार करेंगे हैं। फिलहाल, दिल्ली की रोहिणी अदालत में उनकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई जारी है, जबकि गोवा पुलिस सीबीआई और इंटरपोल के साथ समन्वय में आगे की कार्रवाई कर रही है। मामला बेहद संवेदनशील है और जांच में कई नए पहलू सामने आते जा रहे हैं।

विविध समाचार

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, उज़र प्रदेश समेत छह राज्यों में बढ़ी एसआईआर की समयसीमा, जारी हुआ नया शेड्यूल

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह उज़र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तारीखों में संशोधन कर रहा है।

चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छज़ीसगढ़, उज़र प्रदेश और अंडमान और निकोबार में मतदाता सूची की एसआईआर (स्ङ्क्र) अनुसूची में संशोधन किया गया है। संबंधित मुज़्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों के बाद चुनाव निकाय ने एसआईआर के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात को अब अपनी विशेष गहन

पुनरीक्षण (एसआईआर) रिपोर्ट 19 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 14 दिसंबर, 2025 (रविवार) थी। मध्य प्रदेश, छज़ीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, और नई जमा करने की तिथि 23 दिसंबर, 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गई है, जो पहले की 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) की समय सीमा का स्थान लेगी। उज़र प्रदेश को अब अपनी एसआईआर रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2025 (बुधवार) तक जमा करनी होगी, जो पहले 26 दिसंबर, 2025 (शुक्रवार) थी।

भारत निर्वाचन आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (स्ङ्क्र) का दूसरा चरण चला रहा है। स्ङ्क्रका पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सितंबर में पूरा हो गया था। यह प्रक्रिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छज़ीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उज़र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करती है।

इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने हैं, जहां मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की गई है। इसे %विशेष संशोधन% कहा जा रहा है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम स्ङ्क्र 2002 और 2004 के बीच हुआ था, और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए अंतिम स्ङ्क्रके अनुसार वर्तमान मतदाताओं का मानचित्रण लगभग पूरा कर लिया है। स्ङ्क्रका मुज़्य उद्देश्य जन्मस्थान की जांच करके विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है। बांग्लादेश और ज़्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण हो जाता है।

रोहिंग्या पर ऐसा ज़्या बोल गए सीजेआई सूर्यकांत, बनने लगे निशाना, समर्थन में आए 44 रिटायर्ड जज

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 44 पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या प्रवासी मामले में भारत के मुज़्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ चलाए जा रहे सोची-समझी साजिश की निंदा की है। बयान में कहा गया है कि आलोचकों ने एक सामान्य कानूनी प्रश्न को पूर्वाग्रह के आरोपों में तज़्दील कर दिया है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि सामान्य न्यायिक प्रश्नों को पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियों के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का उद्देश्य न्यायपालिका को कमजोर करना और संवैधानिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करना है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यद्यपि न्यायिक निर्णयों और अदालत में होने वाली चर्चाओं की निष्पक्ष और जानकारीपूर्ण आलोचना की जा सकती है, लेकिन वर्तमान विवाद इस सीमा को पार कर गया है।

न्यायिक कार्यवाहियाँ निष्पक्ष और तर्कपूर्ण आलोचना

के अधीन हो सकती हैं और होनी भी चाहिए। हालाँकि, हम जो देख रहे हैं, वह सैद्धांतिक असहमति नहीं है, बल्कि एक नियमित अदालती कार्यवाही को पूर्वाग्रह से प्रेरित कृत्य बताकर न्यायपालिका को अवैध ठहराने का प्रयास है। मुज़्य न्यायाधीश पर सबसे बुनियादी कानूनी सवाल पूछने के लिए हमला किया जा रहा है-कानूनन, न्यायालय के समक्ष जिस दर्जे का दावा किया जा रहा है, वह दर्जा किसने दिया है? अधिकारों या हकों पर कोई भी निर्णय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि इस सीमा को पहले संबोधित नहीं किया जाता, बयान में कहा गया है।

पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि आलोचकों ने न्यायालय की गलत व्याज़्या की है, और सभी के सज़्मान और सुरक्षा के उसके संदेश की अनदेखी की है। इसी तरह, यह अभियान सुविधाजनक रूप से पीठ की इस स्पष्ट पुष्टि को नज़रअंदाज़ कर देता है कि भारतीय धरती पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को यातना, गुमशुदगी या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं बनाया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सज़्मान किया जाना चाहिए। इसे दबाना और फिर न्यायालय पर अमानवीयकरण का आरोप लगाना, वास्तव में कही गई बात का गंभीर रूप से विरूपण है।

एचआईवी के बढ़ते मामलों से हड़कंप, बिहार के एक जिले में 7400 से ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव, 400 बच्चे भी संक्रमित

सीतामढ़ी ११/१२ (संवाददाता): बिहार के सीतामढ़ी जिले में एचआईवी के मामलों में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जिला अस्पताल के एआरटी केंद्र के अनुसार, अब तक लगभग 7,400 एचआईवी पॉजिटिव मरीज पंजीकृत किए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 400 से अधिक बच्चे हैं, जिन्हें यह संक्रमण अपने माता-पिता से मिला है। एचआईवी संक्रमित बच्चों की उच्च संज़्या ने स्वास्थ्यकर्मियों के बीच चिंता बढ़ा दी है।

डॉज़्टरों का कहना है कि ये मामले मुज़्य रूप से उन परिवारों से संबंधित हैं जहां माता-पिता में से एक या दोनों एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिसके परिणामस्वरूप जन्म के समय ही संक्रमण फैल जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एआरटी सेंटर के चिकित्सा अधिकारियों ने स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है और संक्रमण के बारे में सीमित जन जागरूकता को इस वृद्धि का कारण बताया है।

सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी, जे जावेद ने बताया कि अन्य जिलों में हमसे अधिक एचआईवी के मामले हैं। यह खांसी से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह रक्त आधान या एक ही सुई से इंजेज़्शन लगने से फैलती है। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों में एड्स और एचआईवी के बारे में पढ़ाया जा रहा है... बेतिया, मोतिहारी और मुजज़्फरपुर की स्थिति हमसे भी बदतर है... लगभग 250 से 300 मरीज प्रतिदिन दवा लेने हमारे पास आते हैं; उपचारधीन मरीजों की कुल संज़्या 6,707 है। यह आंकड़े 2012 से अब तक के हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने पूरे जिले में जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। एआरटी केंद्र नए सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शुरू कर रहा है और स्वास्थ्य टीमें स्थानीय गांवों में एचआईवी जांच शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले और पूरे राज्य को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनका कहना है कि सुरक्षित यौन संबंध, दूषित सुइयों के खतरे और नियमित एचआईवी जांच के महत्व के बारे में समय पर जागरूकता फैलाना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। अधिकारियों का मानना ??है कि व्यापक जन जागरूकता और नियमित जांच के बिना सीतामढ़ी में बढ़ते मामलों की स्थिति आने वाले महीनों में और बिगड़ सकती है।

हमलोग तो पीएम बनाना चाहते थे, सीएम ही रह गए नीतीश-अखिलेश

लखनऊ ११/१२ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को पूरा समर्थन देगी। इसके साथ ही अखिलेश ने नीतीश कुमार और पर तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। हम तो नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। उज़र प्रदेश के पूर्व मुज़्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें फिर से मुज़्यमंत्री बनाने का कोई इरादा नहीं है। अपना हमला जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार जी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें फिर से मुज़्यमंत्री नहीं बनाएंगे।

पश्चिम बंगाल उज़र प्रदेश नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा-ममता बनर्जी का भाजपा पर तीखा वार

कोलकाता ११/१२ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में हाल ही में हुए गीता पाठ कार्यक्रम में दो ठेलेवालों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि राज्य में इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नदिया जिले के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुज़्यमंत्री ने कहा कि सभी आरोपियों को गिरज़्तार कर लिया गया है। यह पश्चिम बंगाल है, उज़र प्रदेश नहीं। उन्होंने ठेले बेचने वालों को पीटा... हमने कल रात सभी को गिरज़्तार कर लिया।

बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन की

संस्कृति फैलाने का आरोप लगाया। भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि मैं सांप्रदायिक विभाजन में विश्वास नहीं करती। मैं सभी धर्मों के साथ चलना चाहती हूं। गीता पाठ के लिए सार्वजनिक सभा आयोजित करने की ज़्या आवश्यकता है? जो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या अल्लाह से आशीर्वाद मांगते हैं, वे अपने हृदय में ऐसा करते हैं।धार्मिक ग्रंथों का राजनीतिक लामबंदी के लिए इस्तेमाल करने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो लगातार %गीता, गीता% जपते रहते हैं - श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में ज़्या कहा था? धर्म का अर्थ है पालन करना, विभाजन करना नहीं। वे पश्चिम बंगाल को नष्ट करना चाहते हैं। वे राज्य पर कज़्जा करना चाहते हैं और लोगों को बंगाली बोलने से रोकना चाहते हैं। हम सभी गीता पढ़ते और सुनाते हैं। इसके लिए सभा आयोजित करने की ज़्या आवश्यकता है? कोलकाता पुलिस ने बुधवार रात को तीन लोगों को गिरज़्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने 7 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित पांच लोज़्खो कोंठ गीता पाठ के दौरान दो खाद्य विक्रेताओं पर हमला किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज दो शिकायतों के आधार पर ये गिरज़्तारियां की गईं।

उनके हाथ कांप रहे थे, वे बहुत मानसिक दबाव में हैं..., राहुल गांधी ने फिर गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा, जिन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधार पर बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वे बहुत मानसिक दबाव में हैं। यह सबने कल देखा। मैंने उनसे जो भी पूछा, उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। मैंने उन्हें सीधे तौर पर चुनौती दी है कि वे मैदान में आएं और संसद में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। मुझे कोई जवाब नहीं मिला।

एक अन्य कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी। हरियाणा में जो हुआ, उन्होंने उसके असली सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए। आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, भाजपा ने कांग्रेस और लोकसभा के विपक्ष के नेता पर %हिट एंड रन% की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी हिट एंड रन का फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वे बाहर चले जाते हैं, यही उनकी लोकतंत्र है। उनमें सच सुनने की हिज़्मत नहीं है। कल केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुनकर उन्हें बुरा लगा। मेरा मानना ??है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी होगी... गृह मंत्री के भाषण से पूरा नेहरू परिवार बिखर गया।卐

बुधवार को लोकसभा में तनाव तब बढ़ गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों पर तीखी बहस हुई। गांधी ने बार-बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावे भी शामिल थे। शाह ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, 卐संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी,卐 और जोर देकर कहा कि वे सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे। शाह ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) का भी बचाव किया और इसे मतदाता सूचियों को 卐शुद्ध卐 करने की एक आवश्यक प्रक्रिया बताया। विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे जीतने पर चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हैं और हारने पर उसकी आलोचना करते हैं। यह टकराव शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों के सदन से बाहर चले जाने के साथ चरम पर पहुंच गया, जिसके कारण लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।

पाक सेना का भरोसेमंद, सऊदी अरब में गुप्त मिशन पर भी भेजा गया था, तहव्वुर राणा ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

नयी दिल्ली ११/१२ (संवाददाता):26/11 मुंबई आतंकी हमलों के पीछे मुज़्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर हुसैन राणा ने चौंकाने वाले दावे करते हुए खुलासा किया है कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद ऑपरेटिव था और उसे सऊदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26/11 आतंकी हमले से संबंधित मामले में एनआईए की हिरासत में मौजूद तहव्वुर राणा से पूछताछ की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले से जुड़ी कई जानकारियां पहले से ही आधिकारिक जांच रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहव्वुर राणा अपने पहले के बयानों पर मानसिक रूप से अड़ा हुआ है। अधिकारी ने कहा कि वह पुलिस को जानकारी दे रहा है लेकिन उसके बात करने का तरीका भी उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को दर्शाता है। राणा ने दावा किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद ऑपरेटिव था और इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सऊदी अरब में एक गुप्त मिशन पर भेजा गया था, जिससे पाकिस्तान की सेना के लिए उसके रणनीतिक महत्व पर प्रकाश पड़ा। उसने कहा कि उसने 1986 में आर्मी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की और फिर क्वेटा में कैप्टन (डॉज़्टर) के पद पर नियुक्त हुआ। राणा ने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन-बलोतरा सेज़्टर सहित पाकिस्तान के संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में काम करने का उल्लेख किया। उसने अज़्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे प्रमुख 26/11 साजिशकर्ताओं को जानने की बात स्वीकार की, जो सभी पाकिस्तान से जुड़े थे और मुंबई हमलों में शामिल थे। राणा हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और पश्तो सहित कई भाषाओं में पारंगत है। उन्होंने खुलासा किया कि डेविड हेडली, जो कि अन्य मुज़्य आरोपी है, ने 2003 और 2004 के बीच लश्कर-ए-तैयबा के साथ तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया था।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

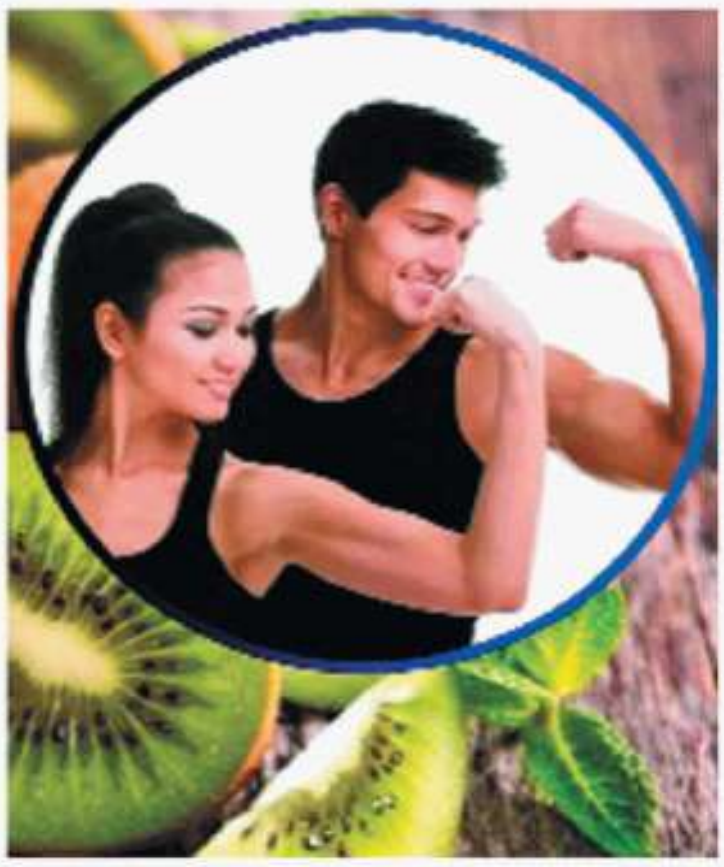

शरीर के लिए लाभप्रद है खट्टी-मीठी कीवी

फलों और सब्जियों के सेवन से स्वास्थ्य को जरूरी पोषक तत्व और विटामिन की पूर्ति होती है। ऐसा ही एक स्वादिष्ट फल है कीवी जिसे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। कीवी में एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, नियासिन, पोटैशियम, राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से रिकवरी करने में बहुत फायदा मिलता है।

गर्भवती महिलाओं के लिए कीवी बहुत फायदेमंद फल है। कीवी में फोलेट की पर्याप्त मात्रा होती है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। गर्भावस्था के दौरान कीवी खाने से बच्चों में न्यूरल डिफेक्ट का खतरा कम होता है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी कीवी का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनमें डिलीवरी के बाद कमजोरी और खून की कमी दूर करने में मदद मिलती है।

डायबिटीज में फायदेमंद

डायबिटीज के मरीजों के लिए कीवी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। कीवी में मौजूद गुण डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद माने जाते हैं। डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह लेकर रोजाना कीवी का सेवन कर सकते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है।

ब्लड क्लॉटिंग को रोके

कीवी के सेवन से शरीर में खून का थक्का जमने की दिक्कत भी नहीं होती है। इसमें एंटीथ्रोम्बोटिक यानी खून का थक्का न जमने देने का गुण मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, किडनी और हार्ट अटैक संबंधी दिक्कत का खतरा भी कम रहता है।

हड्डियों का रखता है ख्याल

कीवी में विटामिन के भी मौजूद होता है, जो ऑस्टियोट्रोपिक एक्टिविटी या नए बोन सेल्स के डेवलपमेंट में योगदान कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन ई, मैग्नीशियम और फोलेट सभी तत्व स्वास्थ्य को कई लाभ प्रदान करते हैं।

कब्ज को दूर करे

कीवी फल, कब्ज को दूर करने में काफी मदद करता है। इसके सेवन से पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक होने लगती है। यह गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, अपच जैसी पेट की दिक्कतों को भी ये दूर करता है। अगर आप भी लगातार कब्ज की बीमारी से परेशान हैं तो कीवी का फल आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पेट साफ करने में भी मददगार है।

हाई बीपी रहता है कंट्रोल में

कीवी में पोटैशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से हृदय स्वस्थ रहता है। साथ ही उच्च रक्तचाप कंट्रोल में रहता है। वहीं, फाइबर बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। एक शोध में उच्च रक्तचाप के मरीजों को एक हफ्ते में 8 किवी खाने की सलाह दी गई है। इसके लिए रोजाना कीवी का सेवन जरूर करें।

क्या आपका भी मिट्टी खाने का मन करता है

पाइका के हो सकते हैं लक्षण

अक्सर आपने बच्चों एवं महिलाओं को बत्ती, चौक या मिट्टी खाते हुए देखा होगा। कई लोगों को मिट्टी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। साथ ही कई लोग इस आदत से परेशान भी होते हैं क्योंकि मिट्टी या चुना आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। यह एक तरह की बीमारी होती है जिसे जियोफेजिया के नाम से जाना जाता है। वैसे मामूली स्थिति में मिट्टी खाने की क्रेविंग कैल्शियम की कमी के कारण होती है लेकिन इसके साथ यह एक बीमारी का भी लक्षण है।

क्या है पाइका

दरअसल मिट्टी खाने का सीधा संबंध पाइका नाम की बीमारी से है। इस बीमारी में इंसान मिट्टी खाने से खुद को रोक नहीं पाता है। ऐसी स्थिति ज्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। इस बीमारी में मिट्टी खाने की लत किसी चीज के नशे के सामान होती है। एक्सपर्ट के अनुसार पाइका एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को उन पदार्थों को खाने की इच्छा होती है जो खाने लायक नहीं है। इस बीमारी का नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। पाइका एक ऐसे पक्षी का नाम है जो कुछ भी खा लेते हैं इसलिए इस बीमारी को पाइका कहा जाता है।

इनकी कमी से होती है मिट्टी खाने की क्रेविंग

इसके साथ ही कई बार मिट्टी खाने का संबंध कैल्शियम की कमी से किया जाता है लेकिन यह एकमात्र ऐसा कारण नहीं है। आयरन की कमी के कारण भी मिट्टी या मिट्टी जैसे पदार्थों को खाने की इच्छा करती है। इस बीमारी में महिलाओं को मिट्टी खाने की बहुत क्रेविंग होती है। ऐसे में जब आप बार बार मिट्टी खाते है तो आपके पेट में बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं।

किडनी स्टोन की हो सकती हैं समस्या

बार बार मिट्टी खाने से आंतों में रुकावट होती है। साथ ही आपके लीवर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि मिट्टी खाने वाले बच्चों और बड़ों के शरीर में सूजन की परेशानी होने लगती है। मिट्टी खाने की वजह से आपका डाइजेशन भी खराब होता है जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता है।

नीमिया की समस्या भी हो सकती है जैसा कि बताया कि आयरन की कमी के कारण भी आपको मिट्टी खाने की समस्या होती है। मिट्टी खाने से इंसान एनीमिया का भी शिकार हो जाता है क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से खून में ऑक्सीजन नहीं जा पाता इस वजह से एनीमिया हो जाता है।

सेहत और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी है हल्दी पानी

हल्दी का उपयोग हर किसी के घर में किया जाता है। हल्दी में एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। हल्दी का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के खाने में किया जाता है। यह व्यंजनों के स्वाद में तो इजाफा करती ही है साथ ही इसमें अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। यह गर्म और रूखी होती है। त्वचा, पेट और शरीर की कई बीमारियों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी का सेवन पानी के साथ किया जाए, तो फायदे बढ़ जाते हैं। हल्दी का पानी सेहत और त्वचा दोनों के लिए लाभकारी होता है। जिन लोगों को बार-बार सर्दी-जुकाम और संक्रमण हो जाता है उन्हें अपनी डाइट में हल्दी के पानी को जरूर शामिल करना चाहिए।

गुणकारी हल्दी के अलग-अलग लाभ उठाने के लिए आपको किसी वैद्य या विशेषज्ञ की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पर ही छोटे-छोटे प्रयोग कर इसके अलग-अलग लाभ उठाए जा सकते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि लोग उठते ही गर्म पानी या फिर निम्बू पानी का सेवन करते हैं जिससे कि उनका पेट साफ़ हो और खुल कर शरीर की गंदगी बाहर निकल जाए यह शरीर के लिए फायदेमंद है, यदि इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी जाए तो इसके गुणों में भारी इजाफा हो जाता है।

शरीर को शक्तिशाली बनाना

लगभग 500 ग्राम की मात्रा में हल्दी की गांठे और एक किलो बुझा हुआ चूना लेकर इसको एक मिट्टी के बर्तन में डालकर इसमें ऊपर से 2 लीटर पानी डालें। पानी डालते ही चूना पकने लगता है और जब यह ठण्डा हो जाए तो बर्तन को ढककर रख दें। इसके बाद 2 महीने बाद हल्दी की गांठों को निकालकर पीसकर चूर्ण बना लें। हल्दी की गांठों के चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में लेकर 10 ग्राम शहद के साथ मिलाकर लगातार 4 महीने तक रोजाना खाने से शरीर का खून साफ हो जाता है और इससे शरीर में भरपूर ताकत आती है।

वजन कम होता है

अगर आप अपना वजन कम करना चाहते है, तो ऐसे में अपनी डाइट में हल्दी का पानी शामिल कर सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। फैट बढ़ाने वाले टिशूज को बनने से रोकने के लिए हल्दी का पानी पीना फायदेमंद होता है।

आंखों के रोग

हल्दी को अरहर की दाल में पकायें और छाया में सुखा लें उसे पानी में घिसकर, शाम होने से पहले ही दिन में दो बार जरूर लगायें इससे झामर रोग, सफेद फूली और आंखों की लालिमा में लाभ होता है।

नहीं होंगी त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं

हल्दी का पानी खून साफ करता है। साथ ही इस पानी को पीने से शरीर में विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इससे एजिंग साइन्स जैसे झुर्रियां या मुरझाई त्वचा की समस्या दूर होगी। त्वचा की सूजन कम करने में हल्दी फायदेमंद मानी जाती है। इसका इस्तेमाल करने से त्वचा में निखार बढ़ता है।

पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी

हल्दी के पानी का सेवन करेंगे, तो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे डायरिया, अपच, कब्ज, पेट में दर्द, पेट में ऐंठन आदि समस्याएं दूर होंगी। हल्दी का पानी पीने से शरीर में पित्त ठीक से बनता है और पाचन तंत्र मजबूत बनता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। हल्दी के पानी का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। हल्दी में मौजूद लिपो पॉलिसैकेराइड की मदद से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सेल्स बढ़ते हैं। एक गिलास गुनगुने पानी में एक नीम्बू निचोड़कर उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें और इसे सुबह खाली पेट पीएं। ऐसा करने से पेट में गैस बनने की समस्या दूर होती है और एसिडिटी, बदहजमी, फूड पॉइजनिंग, कब्ज आदि बीमारी से भी छुटकारा मिलता है जिससे सुबह पेट पानी की तरह साफ होगा।

हार्ट की बीमारियों से होगा बचाव

हल्दी का पानी शरीर से कोलेस्ट्रॉल का स्तर को नियंत्रण रखने में मदद करता है। हल्दी का पानी पीने से खून के थक्के बनने से रोकने में मदद मिलेगी। इससे आपको हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा नहीं होगा।

कम होती है सूजन

शरीर में सूजन कितनी भी क्यों न हो हल्दी सूजन को कम करने में सहायक है इसमें करक्यूमिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो दवा के रूप में काम करता है इसीलिए आपने देखा होगा किसी को भी चोट लग जाती है तो हमारे बुजुर्ग हल्दी दूध में डालकर पिलाते थे।

ब्लाकेज से बचाती है हल्दी

जिन लोगों की खून की धमनियों में ब्लाकेज की शिकायत है उनको तो अवश्य ही हल्दी वाला पानी सेवन करना लाभदायक है क्योंकि हल्दी खून को जमने से रोकती है अदरक भी खून को पतला रखती है और ब्लाकेज से बचाती है।

हड्डी के टूटने पर

हड्डी के टूटने पर रोज हल्दी का सेवन करने से लाभ मिलता है। एक प्याज को पीसकर एक चम्मच हल्दी मिलाकर कपड़े में बांध लें। इसे तिल के तेल में रखकर गर्म करें और इससे फिर सेंक करें। कुछ देर सेंकने के बाद पोटली खोलकर दर्द वाले स्थान पर बांध दें।

नहीं पनपने देती बैक्टीरिया

यदि किसी कारण से शरीर के बाहरी या अदरूनी हिस्से में चोट लग जाए-तो हल्दी वाला दूध उसे जल्द से जल्द ठीक करने में बेहद लाभदायक है क्योंकि यह अपने एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों के कारण बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है।

त्वचा के रोग

हल्दी को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर मालिश करें इससे चर्म रोग खत्म हो जाएगा। या अगर शरीर में खुश्की (चमड़ी सूख) गई हो तो सरसों के तेल में हल्दी को मिलाकर शरीर पर उसकी मालिश करने से लाभ होता है।

मसूढ़ों का रोग

हल्दी को मोटा-मोटा कूटकर आग पर भून लें। इसे बारीक पीसकर कपड़े से छानकर प्रतिदिन सुबह-शाम मसूढ़ों पर मलें। इससे मसूढ़ों के रोग ठीक हो जाते हैं।

सर्दियों में इन आदतों की वजह से बढ़ जाती है कब्ज की परेशानी

सर्दियों में अक्सर लोगों को कब्ज की परेशानी हो जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है ठंड के मौसम में शरीर के फंक्शन में बदलाव आना। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, लेकिन हमारी कुछ आदतें भी हैं जो सर्दियों कब्ज को बढ़ा सकती है। आपका पाचन तंत्र ठीक से काम करें इसके लिए जरूरी है कि आप ठीक प्रकार से हाइड्रेट रहें। वहीं सर्दियों में गर्मी के मुकाबले लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि प्यास ही कम लगती है। पानी की कमी से मल सूखा और कठोर हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में लोग ज्यादातर घर में ही बिताते हैं। शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है और इस वजह से आंतों की गतिविधि धीमी हो जाती है जिससे कब्ज हो सकती है। सर्दी का मौसम सुहावना होता है और इस मौसम में अक्सर लोग तला भुना, भारी खाना खाते हैं जो पाचन क्रिया को और भी धीमा कर देता है। सर्दियों में लोगों के आहार में फाइबर की कमी हो जाती है। लोग सलाद वगैरह कम खाने लगते हैं फाइबर की कमी से भी पाचन धीमा हो जाता है। जिससे कब्ज की समस्या पैदा हो सकती है।

ठंड में लोग चाय कॉफी-अधिक सेवन करते हैं और कैफीन अधिक सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे मल सूखा और कठोर हो जाता है। वहीं सर्दियों के मौसम में लोगों को तनाव और उदासी बनी रहती है। इससे भी पाचन तंत्र प्रभावित होता है। आंतों की गति धीमी हो जाती है। इसके अलावा ठंडी हवा के कारण शरीर की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं जिससे आंतों की गतिविधि में रुकावट आ सकती है।

सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है मल्टीग्रेन आटा

मल्टीग्रेन आटे का अर्थ है मिला जुला आटा या कई तरह के अनाज का मिक्स आटा। इस में गेहू के साथ ही ज्वार, बाजरा, जौ, काला चना, रागी, जई, मक्का, क्विनोआ, सूजी, चावल, सिंघाड़े, राजगिरा आदि के आटे को मिलाकर आटा तैयार किया जाता है। इस आटे में विटामिन, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कार्ब्स, आयरन, कैल्शियम, खनिज आदि कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। मल्टीग्रेन आटा ज्यादातर ग्लूटेन फ्री होता है।

वजन होता है कम

इसके लिए आपको गेहू के आटे में जई, मक्का, ज्वार और चना मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खाना चाहिए। इसमें फाइबर अधिक होने से यह पाचन के लिए ठीक रहेगा और साथ ही यह पेट क्लीन करेगा। यह कई सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ शरीर को संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं जिसके चलते शरीर में विटामिन की कभी कमी नहीं होती है।

पाचन तंत्र को सुधारता

यह फाइबर से भरा होता है जो अच्छे आंत बैक्टीरिया का पोषण करता है, जिसके चलते पाचन तंत्र में सुधार होता है और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार करता है।

शारीरिक दर्द और सूजन को कम करता है बाजरा

बाजरा में सूजन-रोधी गुण होते हैं। मल्टीग्रेन आटा में बाजरे का आटा मिला होने से यह जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभदायक है।

मांसपेशियां होती है मजबूत

इससे मांसपेशियां मजबूत होती है। इस आटे में सोयाबीन, चना और जौ भी मिलाया जाए तो यह प्रोटीन का अच्छा सोर्स बन जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए यह मददगार साबित हो सकता है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

शुक्रवार 12 दिसंबर 2025

एसआईआर पर नया विवाद

चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर का आदेश) दिया था, जो शुरुआत से विवादों में बना रहा। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं विपक्ष ने प्रकट कीं, जिनमें से कई सही भी साबित हुईं। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की चिंताओं का कोई समाधान नहीं किया। वहीं सत्तारुढ़ भाजपा ने भी लगातार एसआईआर को जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग का बचाव किया। भाजपा ने तो यहां तक दावा किया कि विपक्ष घुसपैठियों का साथ दे रहा है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज तक यह नहीं बताया है कि उसे कितने घुसपैठिए मतदाता के तौर पर मिले हैं। बहरहाल, एसआईआर पर उठ रहे कई तरह के सवालों के बीच अब एक बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। जिसके बाद चुनाव आयोग का फैसला और नीयत दोनों पर तत्काल सफाई पेश किए जाने की जरूरत है। क्योंकि एसआईआर में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि नागरिकों से उनके मतदान का हक छीना जा रहा है। यह चिंता इस खुलासे के बाद और गहरा गई है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा किया है। श्री संधु ने आदेश के ड्रा ट संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी। जो हटा दी गई है। चुनाव आयुक्त संधु ने ड्रा ट आदेश की फाइल में लिखा था- यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता/नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब एसआईआर के लिए वैध दस्तावेज की सूची जारी की गई, तो सबसे ज्यादा तकलीफ में गरीब ही आए। बिहार से ऐसी ढेरों खबरें आईं, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल भी पूछा गया कि आधार को दस्तावेज लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। दो बार की मौखिक सलाह के बाद तीसरी बार अदालत को भी आधार शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को स त लहजे में कहा गया। अब श्री संधु की टिप्पणी के बाद समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग में भी नागरिकता बचाने पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। ये और बात है कि उस चिंता को जाहिर नहीं होने दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे किसका दबाव था, क्या चुनाव आयुक्तों में मतभेद है, क्या मु य चुनाव आयुक्त ने अपने साथी चुनाव आयुक्त द्वारा व्यक्त की गई चिंता की उपेक्षा की, ऐसे कई सवाल इस खुलासे के बाद उठ रहे हैं। मु य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाद में उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्रा ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था। ड्रा ट आदेश में लिखा था कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 (नागरिकता अधिनियम) के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हों। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था और उसके बाद देशभर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित तथा 2004 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ हटा दिए गए। उसकी जगह लिखा गया-चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फलस्वरूप, आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही..। यह पैराग्राफ अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है, वाक्य सेमिकोलन के बाद अधूरा रह जाता है। अब तक चुनाव आयोग ने इस अधूरी लाइन पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर वो लाइन अधूरी क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसने 28 नवंबर को आयोग के प्रवक्ता से दोनों आदेशों में हुए बदलाव के बारे में पूछा था, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं मिली।

मोदी-पुतिन शिखर वार्ता ने दी भारत की भूराजनीतिक पहचान को नई ऊंचाई

नित्य चक्रवर्ती

रूस और भारत के संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की अपनी साझा इच्छा की फिर से पुष्टि की, जिसमें रूस को भारत का निर्यात बढ़ाना, औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करना, नई प्रौद्योगिकीय और निवेश साझेदारी बनाना, खासकर विकसित उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और परस्पर सहयोग के नए रास्ते और तरीके खोजना शामिल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दो दिन की बातचीत के बाद 5 दिसंबर को जारी भारत-रूस संयुक्त बयान ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के दस्तावेज से कहीं अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतों के दबाव को नज़रअंदाज़ करते हुए भारत के भूराजनीतिक हैसियत और पहचान को फिर से इस्तेमाल करने की पुष्टि है।

इस दौरे का समय और इसके बाद 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली एयरपोर्ट के टरमैक पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सामान्य निर्धारित राजकीय व्यवहार (प्रोटोकॉल) को नज़रअंदाज़ करते हुए राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत, उन सभी बातों को दिखाता है जो नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका की लगातार चेतावनी को कोई अहमियत न देते हुए राजनयिकता में एक अलग रास्ता चुनने के लिए सावधानी से लेकिन पक्के इरादे से काम किया है।

1 दिसंबर को एक अजीब बात हुई जब नई दिल्ली में मौजूद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के तीन राजदूतों ने मिलकर द टाइ स ऑफ इंडिया में रूसी राष्ट्रपति की कड़ी आलोचना करते हुए एक लेख लिखा, जैसे-जैसे राष्ट्रपति पुतिन गंभीर शांति बातचीत में देरी कर रहे हैं, हम यूक्रेन को अपनी मिलिट्री और नॉन-मिलिट्री मदद बढ़ाते रहेंगे ताकि वह अपने लोगों, अपनी ज़मीन और अपनी आज़ादी की सही तरीके से रक्षा कर सके'। यह मिला-जुला लेख इस यूरोपियन तिकड़ी की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में दबाव डालने के लिए एक खुली दखलअंदाज़ी के अलावा और कुछ नहीं था।

यूरोपियन तिकड़ी और वाशिंगटन डीसी के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी की बात थी, जहां ट्रंप के अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के हर व्यवहार पर नज़र रख रहे थे। भारतीयों के लिए यह देखना बहुत सुकून देने वाला था कि हमारे प्रधानमंत्री रूसियों के साथ धीरे चलने के पश्चिमी दबाव की परवाह किए बिना सावधानी से लेकिन इज्ज़त से पेश आ रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता अपने आखिरी चरण में है। यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौता भी अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप हासिल करने के लिए तैयार है। पश्चिम के लिए कुछ भी काम नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री ने 1.44 अरब लोगों के नेता के तौर पर पूरे आत्मविश्वास के साथ रूसी राष्ट्रपति से बात की, एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और जिसकी मज़बूत अर्थव्यवस्था 2027-28 तक अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है।

यह भारत की तरफ से बड़ी वैश्विक ताकतों के सामने अपनी रणनीतिगत स्वायत्तता दिखाने का एक मज़बूत संकेत है। अमेरिका भारत की रणनीतिगत स्वायत्तता की इज्ज़त नहीं करता। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने भारत के खिलाफ़ प्रतिबंधों के मामले में बार-बार इस बात का ज़िक्र किया है। जहां तक रूस की बात है, भारत के लिए स्वायत्तता का यह हिस्सा सोवियत यूनियन के दिनों से चला आ रहा है। हाल ही में नई दिल्ली शिखर स मेलन में नरेंद्र मोदी और पुतिन दोनों ने इस बात पर ज़ोर दिया और यह इस वर्तमान चरण में भारतीय कूटनीति का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू था। अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत को बिना रुकावट

इसके अलावा, दोनों पक्ष अपने सहयोग को जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, वित्तीय संदेश प्रदातृ प्रणाली आदि के साथ ही दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म की पारस्परिक संचालनीयता को चालू करने पर बातचीत पर भी सहमति बनी है। ज़्यादा जानें राजस्थान समाचार हरियाणा समाचार बॉलीवुड समाचार पत्रिका टैबलेट मनोरंजन समाचार सेवा क्षेत्रीय समाचार अलर्ट बॉलीवुड न्यूज़ मनोरंजन समाचार समाचार ऐप बिहार समाचार सच तो यह है कि 2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने के इस लक्ष्य पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन पहले बताए गए फॉलो-अप उपाय कई वजहों से नहीं किए गए हैं।

तेल आपूर्ति का भरोसा एक ऐसी गारंटी है जो अमेरिका समेत दूसरे खनिज तेल निर्यातक देशों के साथ भारत की मोलभाव करने की ताकत को बढ़ा सकती है। अमेरिका अब रूस के निर्यात की कीमत पर भारत पर अमेरिका से ज़्यादा तेल उत्पादन आयात करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारतीय एजेंसियों ने पहले ही रूसी स्रोत से आपूर्ति कम कर दी है।

रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियां अमेरिका के प्रतिबंध का पूरी तरह पालन कर सकती हैं, लेकिन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास चुनने की आज़ादी है और रूस के भरोसे के बाद यह और बढ़ेगी। भारत के पास खनिज तेल के आयात का स्रोत चुनने का विकल्प है, और इससे खरीद की टोकरी बड़ी होगी। ज़्यादा जानें युवा समाचार पत्र समाचार पत्र सदस्यता खेल जगत अपडेट क्षेत्रीय समाचार अलर्ट मनोरंजन समाचार सेवा मनोरंजन समाचार कविता संग्रह छत्तीसगढ़ समाचार समाचार ऐप हिंदी समाचार सदस्यता रूस और भारत के संयुक्त बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने संतुलित और टिकाऊ तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की अपनी साझा इच्छा की फिर से पुष्टि की, जिसमें रूस को भारत का निर्यात बढ़ाना, औद्योगिक सहयोग को मज़बूत करना, नई प्रौद्योगिकीय और निवेश साझेदारी बनाना, खासकर विकसित उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और परस्पर सहयोग के नए रास्ते और तरीके खोजना शामिल है।

दोनों नेताओं ने विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए एक खुले, सबको साथ लेकर चलने वाले, पारदर्शी और बिना भेदभाव वाले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व पर ज़ोर दिया।

दोनों पक्षों ने जिन बातों पर ज़ोर दिया उनमें टैरिफ और नॉन-टैरिफ व्यापार की रुकावटों को दूर करना, लॉजिस्टिक्स में रुकावटों को दूर करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, आसान भुगतान प्रणाली पक्का करना, बीमा और पुनर्बीमा के मामलों के लिए आपसी सहमति वाले हल ढूंढना और दोनों देशों के व्यवसाय के बीच नियमित रूप से बातचीत, 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डालर के बदले हुए द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में हासिल करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, रूस और भारत द्विपक्षीय व्यापार को बिना किसी रुकावट के बनाए रखने के लिए अपनी-अपनी राष्ट्रीय करेंसी के इस्तेमाल से द्विपक्षीय भुगतान के मामलों को सुलझाने की प्रणाली को मिलकर विकसित करते रहने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा, दोनों पक्ष अपने सहयोग को जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, वित्तीय संदेश प्रदातृ प्रणाली आदि के साथ ही दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म की पारस्परिक संचालनीयता को चालू करने पर बातचीत पर भी सहमति बनी है। ज़्यादा जानें राजस्थान समाचार हरियाणा समाचार बॉलीवुड समाचार पत्रिका टैबलेट मनोरंजन समाचार सेवा क्षेत्रीय समाचार अलर्ट बॉलीवुड न्यूज़ मनोरंजन समाचार समाचार ऐप बिहार समाचार सच तो यह है कि 2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के 100 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने के इस लक्ष्य पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, लेकिन पहले बताए गए फॉलो-अप उपाय कई वजहों से नहीं किए गए हैं। मोदी राज में भारत का फोकस अमेरिकी बाजार और निवेश पर था, तथा रूसी मार्केट को लंबे समय तक नज़रअंदाज़ किया गया।

इसे दोनों तरफ से ठीक करना होगा। दिल्ली समिट को भारत-रूस रिश्तों की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के मामले में गेम चेंजर के तौर पर काम करना चाहिए। नहीं तो, सभी घोषणाओं और समझौतों के बावजूद व्यापार और निवेश में वही ठहराव बना रहेगा, जो निकट अतीत में रहा है। भारत सरकार के लिए, यह समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ आने वाली बातचीत में इस दौरे से मिले फायदों का रणनीतिगत तरीके से सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का है।

चीन पहले ही पुतिन के साथ मोदी की बातचीत का स्वागत कर चुका है। हर एक के लिए रणनीतिगत स्वायत्तता के आधार पर भारत-चीन-रूस साझेदारी बनने की अच्छी संभावना हो सकती है। कुल मिलाकर, हाल ही में हुए भारत-रूस शिखर स मेलन समिट के बाद भारतीय राजनयिकता के पास और मज़बूत होकर उभरने का एक बड़ा मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने बढ़े हुए रुतबे के साथ, यह देखना होगा कि ये कूटनीतिक फ़ायदे फिर से बर्बाद न हों।

खनन से खत्म होते पहाड़?

सुरेश भाई

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी यहां खनन कार्य में लगी भारी मशीनों और उनसे उत्पन्न ध्वनि-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण सहित कई नकारात्मक प्रभावों की अनदेखी की है जिससे खनन कारोबार को अधिक बल मिला है। कई स्थानों पर अनुमति न मिलने के बाद भी खनन होता रहा है जिससे खनन प्रभावितों को ल बे समय तक आंसू बहाने पड़े हैं।

मनुष्य अपने जीवन की अंतहीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती मां के किसी भी भाग से अपने लालच के लिए जल, जंगल, जमीन और उसके पेट से खनिज पदार्थों का इतना अधिक दोहन कर लेता है कि वह किसी दूसरे प्राणी के जीवन और जीविका के हिस्से को भी बर्बाद करके कोई पछतावा नहीं करता। इसका जीता-जागता उदाहरण है, उत्तराखंड। राज्य के 13 जिलों में से एक बागेश्वर है जहां पर पिछले डेढ़ दशक से एक ही स्थान पर बार-बार खड़िया खनन का काम चल रहा था। इसके दुष्प्रभाव से यहां के कांडा तहसील के दर्जनों गांवों में पीने का पानी सूख गया है। खेतों और गांव में दरारें आयी हैं। गांव के पाले हुए जंगल काट दिये गये हैं। ढालदार पहाड़ियों पर अंधाधुंध खड़िया खनन से भूस्खलन होने लगा है।

लोगों के आवागमन के रास्ते ध्वस्त कर दिये गये हैं जिससे महिलाओं को अपने पशुओं के लिए चारा लाना भी कठिन हो गया है। यहां खनन प्रभावित गांवों के लोगों ने अपनी बात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का जोरदार काम किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया।

कई बार जब लोग अपनी समस्याओं को लंबे समय तक उठाते रहते हैं तो न्यायपालिका ध्यान देती है। इसका एक सराहनीय उदाहरण है -नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका के रूप में खनन प्रभावितों की बात को सुनने का फैसला किया है। काबिले गौर है कि अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 नवंबर 2024 को संज्ञान लेते हुए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया था जिनके द्वारा उच्च न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

इस रिपोर्ट में जिन तथ्यों को उजागर किया गया है उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जि मेदार स्थानीय प्रशासन ने मूक दर्शक होकर खनन के मालिकों को पनाह दी है जिससे लोगों को अपने जल, जंगल, जमीन से बेदखल होना पड़ा है। प्रभावित गांवों के लोग लंबे समय तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे, परन्तु उन्होंने कभी उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस पर कोर्ट कमिश्नरों की जांच टीम ने प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन करके बताया है कि आबादी वाले क्षेत्रों में पहाड़ियों को नीचे से खोदकर होने वाले भूस्खलन रोकने के लिए किसी भी तरह की रिटेनिंग वॉल और अन्य सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गये हैं।

अवैज्ञानिक तरीके से खनन कार्य में खदानों की सीमाओं पर हरित पट्टी और खनन योजना में सावधानी रखने के लिए जो नियमानुसार प्रस्तावित गतिविधियां हैं उन्हें धरातल से गायब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे बफरजोन, ढलान पर्यवेक्षण, सुरक्षात्मक ढांचे, जल निकास और जल प्रबंधन की कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी। खनन प्रभावित गांवों में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, पठाल के मकान हो या आधुनिक सीमेंट-कांक्रीट, दोनों प्रकार के मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं जिसके चलते लोगों की रातें खौफ में गुजर रही हैं। यहां की धरती भूकंप से कांपती रहती है।

यहां खनन के मालिकों ने लोगों का जीना तो हराम किया ही है, साथ ही उन्होंने खनन कार्य के दौरान बच्चों से भी निडर होकर काम करवाया है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार रमेश पांडे %कृषक% ने जानकारी दी है कि जहां वयस्क लोग भी नहीं जा सकते, वहां बच्चों को खड़िया निकालने के लिए संकरी दरारों के भीतर भेजा जाता है। इसके अलावा चिंताजनक है कि खदानों में काम करने वाले मजदूरों को हेलमेट, बूट आदि उपकरण, जो निरंतर उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे, उस पर भी गैर-जि मेदारी बरती गयी है।

खनन जैसे मामलों में %पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट% को लोग जानना पसंद करते हैं, लेकिन यहां तो इस विषय में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। %राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी% ने क्षेत्र में खनन कार्यों के लिए 373 स्वीकृतियां दी हैं, जबकि उनके पोर्टल पर 68 फाइलों को ही अपलोड किया गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए जि मेदार एजेंसी के द्वारा अपने दायित्व के प्रति सूचनाओं को छुपाना बहुत चिंतनीय है और खुले रूप में यह पर्यावरण के प्रति अनदेखी है। कोर्ट कमिश्नरों की जांच के दौरान खनन प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह दिन में खनन कार्य बंद करके रखा जाता है और उनके लौटते ही रात भर खनन का काम चलता रहता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड% ने भी यहां खनन कार्य में लगी भारी मशीनों और उनसे उत्पन्न ध्वनि-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण सहित कई नकारात्मक प्रभावों की अनदेखी की है जिससे खनन कारोबार को अधिक बल मिला है। कई स्थानों पर अनुमति न मिलने के बाद भी खनन होता रहा है जिससे खनन प्रभावितों को ल बे समय तक आंसू बहाने पड़े हैं।

नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन कारोबारी और उनको नियंत्रित करने वाली जि मेदार व्यवस्था की इस गैर-जि मेदाराना स्थिति के आकलन के बाद 6 जनवरी 2025 को बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी 9 जनवरी को दूसरी सुनवायी की गई, जिसमें बागेश्वर के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। उच्च अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया कि वन भूमि के अलावा सरकारी भूमि पर भी खनन कारोबारियों ने नियम विरुद्ध काम किया है जिसके बाद ही 160 पट्टाधारकों को नोटिस जारी किए गए और यहां पर काम में लगी दर्जनों पोकलेन और जेसीबी मशीनों को जब्त भी किया गया। उत्तराखंड पर्यावरण विभाग से भी इस पर जवाब मांगा गया।

इस पूरे घटनाक्रम में समझा जा सकता है कि पर्वतीय इलाकों में निवास करने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों की छोटी-छोटी जोत और उनके प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की ओर मौजूदा व्यवस्था का ध्यान नहीं है। यह भी उदाहरण है कि %मातृ सदन, हरिद्वार% के तीन संतों ने खनन के खिलाफ अपनी जान न्यौछावर की है। खनन के पट्टे ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिसकी कोई मॉनिटरिंग करने की हि मत नहीं कर सकता। नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण उदाहरण खनन प्रभावितों के हितों में किया है। इससे पर्यावरण को भी अदालत में न्याय मिला है, दूसरी ओर कल्याणकारी व्यवस्था को अपनी गैर-जि मेदारी का अहसास हुआ है।

(लेखक %उत्तराखण्ड सर्वोदय मंडल% के अध्यक्ष हैं। वे %उत्तराखण्ड नदी बचाओ अभियान% से भी जुड़े हैं।)

विविध समाचार

सीएम मान द्वारा दक्षिण कोरिया के व्यापारिक दिग्गजों से विचार–विमर्श, पैंग्यो टेक्नो वैली की तर्ज पर मोहाली को विकसित करने की घोषणा

चंडीगढ ११/१२ (संवाददाता): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दक्षिण कोरिया की अग्रणी कंपनियोंकृ डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण, जी.एस. इंजीनियरिंग एवं निर्माण, नॉन्गशिम, कोरिया रक्षा उद्योग संघ, सियोल व्यवसाय एजेंसी तथा अन्य अनेक कंपनियोंकृको राज्य में निवेश करने का आमंत्रण दिया। दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण के चेयरमैन जंग वॉन जू से मुलाकात की और नवोन्मेषी ऊर्जा परियोजनाओंकृसमुद्री पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादनकृमें सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढाँचेकृतरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल, पेट्रो–रासायनिक परिसर, उर्वरक संयंत्रकृतथा आधुनिक आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं, स्मार्ट नगर परियोजनाओं, और सड़क, पुल, रेल, बंदरगाह व हवाई अड्डों से संबंधित सिविल ढाँचे में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री ने मॉड्यूलर तथा पूर्व–निर्मित ढाँचों की आधुनिक निर्माण तकनीक में तकनीकी आदान–प्रदान की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि तेज और किफायती निर्माण मॉडल विकसित किए जा सकें। डैवू इंजीनियरिंग एवं निर्माण जैसी विश्वविख्यात अवसंरचना कंपनी के साथ रणनीतिक बैठक के दौरान उन्होंने पंजाब की मजबूत औद्योगिक गति, आधुनिक बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु चल रहे प्रमुख प्रयासों तथा "निवेश पंजाब" प्रणाली के अंतर्गत विशेष संयुक्त निरीक्षण ढाँचे की जानकारी साझा की। उन्होंने वैश्विक उद्योग समूह को पंजाब में व्यापक आधारभूत विकास, आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रस्तावित औद्योगिक नगरों में संभावनाओं की खोज करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने पर्यावरण–अनुकूलता के वैश्विक मानकों के अनुरूप चलने वाली पहलोंकृईएसजी प्रतिबद्धताओं और हरित हाइड्रोजन कार्यक्रमोंकृमें साझा प्रयासों पर भी जोर दिया। इसके बाद हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जी. एस. इंजीनियरिंग एवं निर्माण के वाइस चेयरमैन यंग हा र्यु से मुलाकघत की। उन्होंने सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसी नव्य ऊर्जा परियोजनाओंय सड़क, पुल और स्मार्ट नगर जैसी आधारभूत परियोजनाओंय तथा औद्योगिक परिसरों एवं अभिकल्प –खरीद–निर्माण (ई.पी.सी.) सेवाओं के क्षेत्र में समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मॉड्यूलर निर्माण तकनीक और हरित हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशाल संभावनाओं का उल्लेख किया और राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। नॉन्गशिम होल्डिंग्स के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में संयुक्त कार्य का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारतीय स्वादानुसार नवीन त्वरित–पकवान (इंस्टैंट) नूडल्स के नए संस्करण विकसित करने की आवश्यकता बताई, साथ ही भारत की सुपरमार्केट श्रृंखलाओं और ई–वाणिज्य मंचों पर इनके वितरण के विस्तार पर भी चर्चा की। उन्होंने युवा वर्ग और स्वास्थ्य– सचेत उपभोक्ताओं तक ब्रांड की पहुँच बढ़ाने, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ पर्यावरण– हितैषी पैकेजिंग समाधान विकसित करने तथा दीर्घकालिक उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ और पौध ा–आधारित विकल्पों पर अनुसंधान में साझेदारी की वकालत की। कोरिया रक्षा उद्योग संघ (के डी आई ए) के वाइस चेयरमैन ली सुंग क्यू से बातचीत में मुख्यमंत्री ने रक्षा निर्माण, रक्षा–तकनीक के आदान–प्रदान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और मानव–रहित प्रणालियों जैसी उन्नत सैन्य तकनीकों में सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने सायबर सुरक्षा तथा कौशल–विकास कार्यक्रमों में साझा प्रयास करके रक्षा निर्माण क्षेत्र में दक्ष जनशक्ति तैयार करने की संभावनाओं पर भी बल दिया। सियोल व्यवसाय एजेंसी के स्टार्टअप प्रभाग के निदेशक जोंग वू किम के साथ मुलाकघत के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब–आधारित नवोन्मेषी उद्यमों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने हेतु उनके त्वरक (एक्सलेरेशन) और इंक्यूबेशन कार्यक्रमों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी–तंत्र, अनुसंध ाान–विकास, नवाचार–संस्कृति तथा उत्पाद–प्रमाणीकरण (जैसे "सियोल पुरस्कार") में साझेदारी को समय की आवश्यकता बताया। इसके बाद आयोजित पंजाब में व्यवसाय सुगमता पर गोलमेज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया की अग्रणी वाणिज्यिक, निवेश और उद्योग कंपनियोंकृबी.के.एल., यूलचोन, बडट्री प्रबंधन समूह, एस.के. प्रतिभूति, किम एंड चांग, शिन एंड किम, ली एंड को, डेन्टन्स ली, कोरिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, कोरिया रोबोट उद्योग संघ, कोरिया व्यापार–निवेश प्रोत्साहन संगठन, कोरिया ऑटो–भाग उद्योग सहकारी, युआन्टा प्रतिभूति, कैपस्टोन परिसंपत्ति प्रबंधन, एन.एच. निवेश एवं प्रतिभूति, और कोरिया औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं व्यापार संस्थानकृके प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पंजाब को सर्वाधिक उपयुक्त निवेश स्थान बताते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई प्रमुख सुधार पहलों से इन्हें अवगत कराया और उद्योग विकास को और सहज बनाने हेतु सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री ने एशिया के सबसे उन्नत नवाचार–केंद्रों में से एक पैंग्यो टेक्नो वैलीकृजिसे "कोरिया की सिलिकॉन वैली" कहा जाता हैकृका अवलोकन भी किया। ग्योंगगीदो व्यवसाय एवं विज्ञान त्वरक के अधिकारियों ने उन्हें पैंग्यो के एकीकृत मॉडल, तकनीकी नवोन्मेष, स्टार्टअप संस्कृति और उच्च–मूल्य अनुसंधान की प्रणाली के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार 1,780 से अधिक कंपनियों, 83,000 पेशेवरों और 25,000 शोधकर्ताओं वाला पैंग्यो विश्व–स्तरीय नवोन्मेषिक क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने पैंग्यो के संरचित त्वरक कार्यक्रमों, विशेष परीक्षण सुविधाओं और प्रदर्शन–आधारित मूल्यांकन पद्धतियों की विशेष प्रशंसा की और कहा कि मोहाली में भी ऐसे मॉडल अपनाकर स्टार्टअप पारिस्थितिकी, अनुसंधान–विकास और कौशल–आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने मोहाली को व्यापक विकास देकर उसे नवाचार–केंद्र के रूप में उभारने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विस्तृत संभावनाओं द्वारा पंजाब सरकार ने कोरियाई कंपनियों का स्वागत करने, नवाचार–आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने और दीर्घकालिक पारस्परिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता और अधिक सुदृढ़ की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में निर्माण, प्रौद्योगिकी, खाद्य–प्रसंस्करण, अनुसंधान एवं विकास सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सियोल रोड–शो "प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन–2026" से पूर्व यह सम्पूर्ण कार्यक्रम वैश्विक निवेशकों को पंजाब में तीव्र आर्थिक–औद्योगिक अवसरों से अवगत कराने का एक प्रमुख माध्यम है।

अब प्राइवेट स्कूलों में भी फेल होंगे पांचवीं और आठवीं के छात्र, सरकार ने लागू किया नियम

शिमला११/१२ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी निजी स्कूलों में भी पांचवीं और आठवीं कक्षा में फेल होने की व्यवस्था लागू कर दी है। अब कम अंक आने पर निजी स्कूलों के विद्यार्थी भी परीक्षा में असफल माने जाएंगे। यह प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में संशोधित किए गए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को प्रदेश में लागू करने के बाद संभव हुआ है। नई व्यवस्था के तहत, परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने के लिए एक और अवसर दिया जाएगा। यदि छात्र दूसरी बार भी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे फेल घोषित कर अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में यह नियम दिसंबर 2025 की परीक्षाओं से लागू होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में यह प्रावधान मई 2026 की परीक्षाओं में लागू होगा। सरकारी स्कूलों में यह प्रणाली पिछले वर्ष ही लागू कर दी गई थी। अब निजी स्कूल भी उसी प्रणाली का पालन करेंगे। संशोधित अधिनियम के अनुसार छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करने के लिए निम्न दो मानक पूरे करना आवश्यक होंगेकृ समग्र रूप से कम से कम 33ः अंक प्राप्त करना। एसए–1 और एसए–2 के प्रत्येक विषय में अलग–अलग न्यूनतम 33ः अंक लाना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए सभी जिलों को विस्तृत दिशा–निर्देश भेज दिए हैं।

यमुनानगर में मिली महिला की नग्न सिर कटी लाश, शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स, सिर गायब

यमुनानगर ११/१२ (संवाददाता): हरियाणा के यमुनानगर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब जगाधरीदृपांवटा नेशनल हाईवे से सटी पॉपलर पौधों की नर्सरी में एक युवती की नग्न अवस्था में सिरकटी लाश बरामद हुई।

शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। नर्सरी संचालक ने खेत में पानी देने के लिए पहुँचते ही शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, मृतका की उम्र लगभग 25 साल प्रतीत हो रही है। उसके शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, जबकि सिर कहीं नहीं मिला। पुलिस आसपास के पूरे क्षेत्र में युवती के सिर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा है। सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी मौके पर पहुँचकर साक्ष्य जुटाए तथा घटनास्थल की बारीकी से जांच की। वहीं, हत्यारों तक पहुँचने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की सहायता भी ली है।

पुलिस ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए हत्यारों की तलाश तेज कर दी है और प्रारंभिक जांच में किसी अन्य स्थान पर हत्या कर शव को यहाँ फेंके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों को कहना है कि जिस तरह से युवती की लाश मिली है, उसके साथ गलत काम किए जाने का भी अंदेशा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि युवती के साथ हत्या से पहले कुछ गलत भी हुआ होगा, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसका खुलासा पोस्टमॉर्टम के बाद ही हो पाएगा। पुलिस ने युवती की पहचान कराने के लिए आसपास के थानों में उसके फोटो भेज दिए है।

लुधियाना में दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 5 की मौत, मरने वालों में 2 नाबालिग लड़कियां

लुधियाना ११/१२ (संवाददाता): पंजाब के लुधियाना में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इसमें हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रविवार देर रात हुआ। देर रात 1 बजे 2 एंबुलेंस में शवों को सिविल अस्पताल लाया गया। फिलहाल किसी की भी पहचान नहीं हो सकी है। मृतकों में 2 नाबालिग लड़कियां और 3 युवक थे। मरने वाले सभी जगराओं के बताए जा रहे हैं। हालांकि इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। जानकारी के मुताबिक वरना कार नंबर PB10DH–4619 साउथ सिटी की तरफ से लाडोवाल जा रही थी। ओवर स्पीड के कारण कार बेकाबू होकर लाडोवाल में डिवाइडर से टकराकर सड़क के बीच पलट गई और काफी दूर तक घसीटते चली गई। हादसे में पांचों शव क्षत–विक्षत हो गए। सूचना मिलते ही थाना लाडोवाल से ASI कश्मीर सिंह मौके पर पहुंचे और तुरंत एनएचएआई की एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंच गई और शवों को कार से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ले जाया गया।

वंदे मातरत पर चर्चा : सवाल नीति और नीयत का

भारतीय संसद में शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान ष्वंदे मातरमष् की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक विशेष चर्चा आयोजित की गयी। गौर तलब है कि संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण से तैयार किया गया यह गीत पहली बार 1882 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उनकी बांग्ला उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसी गीत अर्थात ष्वन्दे मातरम्ष् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आज देश में इस गीत को भी राष्ट्रगान अर्थात ष्जन गण मनष् के ही समकक्ष सम्मान प्राप्त है। सभी सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में जब इसे गाया या बजाया जाता है, तो सभी लोग इसके सम्मान में खड़े होते हैं। परन्तु हमारे देश में मुस्लिम उलेमा का एक वर्ग ऐसा है जिनका मानना है कि धरती–माँ को इस तरह देवी के रूप में पूजना और उसके सामने सजदा करना इस्लाम विरोधी (शिर्क) है। और अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना हराम है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व खासतौर पर देवबंदी अथवा जमाअत–ए–इस्लामी से सम्बंधित अतिवादी वर्ग के लोग ही करते हैं। जबकि अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रप्रेम का हिस्सा मानते हुये इसे गाते भी हैं। परन्तु राष्ट्रगान ष्जन गण मनष् का विरोध करने वाले हिंदूवादी विचारधारा से जुड़े लोग खासकर संघ व भाजपा वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का इलजाम लगाती रहती है। यही कोशिश गत दिनों संसद में ष्वंदे मातरमष् पर चर्चा के दौरान देखने को भी मिली। खासकर इस चर्चा का ऐसे समय में होना जबकि अगले वर्ष बंगाल में चुनाव भी प्रस्तावित हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ष्वंदे मातरमष् पर बहस के दौरान सरकार पर तीखा प्रहार करते हुये यह कहा भी कि राष्ट्रगान पर बहस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यह पहले से ही राष्ट्रगान है। प्रियंका गांधी ने भी यही दावा किया कि यह चर्चा बंगाल चुनावों को ध्यान में रखकर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने ष्वंदे मातरमष् को भारत की आत्मा का हिस्सा बताया, जो गुलामी से जागरण का प्रतीक है और आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है। उल्टे प्रियंका गांधी ने संविधान सभा में दो छंद अपनाने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरोध न करने का ही सवाल उठा कर भाजपा को ही घेरने की कोशिश की। राजयसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सत्ता से सवाल किया कि जब भाजपा के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहां थी? बहरहाल,इसी तरह के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बताने व हमेशा ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली भाजपा को कम से कम देश को एक बात यह भी बतानी चाहिये कि जिस दारुल उलूम देवबंद व जमाअत–ए–इस्लामी ने वंदे मातरम का विरोध किया था, जिस जमीयत उलेमा–ए–हिंद ने 1937–39 में जारी अपने फतवे में वंदे मातरम को गाना श्हरामश बताया था। उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से तो भारत बेहतर रिश्ते बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है ? गत अक्टूबर माह में ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने भारत का छह–दिवसीय दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुत्तकी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता, शिक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से संभव यह यात्रा भारत– अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने का संकेत मानी गई। मुत्तकी ने अपने भारत प्रवास के दौरान केवल राजकीय यात्रा मात्र ही नहीं की बल्कि इस दौरान उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित दारुल उलूम देवबंद अर्थात अपने श्वैचारिक प्रेरणा केंद्रश का भी दौरा किया। यह वही दारुल उलूम देवबंद तो है जिसने वंदे मातरम के एक हिस्से को गाने का विरोध किया था ? मुत्तकी ने अपने भारत दौरे के बीच दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर व देवबंदी मसलक से जुड़े दारुल उलूम के उलेमा, छात्रों और अफगान छात्रों से मिकर केवल अपनी अतिवादी वैचारिक प्रतिबद्धता ही नहीं दोहराई बल्कि उन्होंने दिल्ली में ही आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को प्रवेश न देकर भी यह साबित कर दिया कि महिलाओं के प्रति इस सोच विचार के लोग कितनी असहिष्णुता का भाव रखते हैं। परन्तु आश्चर्य है कि भाजपा सरकार वंदे मातरम गायन का विरोध करने व इसे हराम बताने वाली विचारधारा व इसके रहनुमाओं को तो गले से लगाती है। इनके स्वागत में लाल कालीन बिछाती है परन्तु कांग्रेस पर वंदे मातरम विरोधी होने का आरोप मढ़ती है ? परन्तु जब कांग्रेस संविधान सभा में इस गीत के दो छंद अपनाने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरोध न करने का सवाल उठाती है तो भाजपा बगलें झाँकने लगती है ? आज देश बेरोजगारी व मंहगाई से बुरी तरह जूझ रहा है। डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत रसातल तक पहुँच गयी है। 2012–13 के मध्य जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 60–68 के बीच लुढ़क रही थी। उस समय नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा था कि ष्हमारी मुद्रा मृत्युशैया पर है, यह टर्मिनल स्टेज पर है और इसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत हैष्। उसी समय मोदी ने जोर देकर यह भी कहा था कि रुपये की गिरावट से प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, क्योंकि रुपया केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। उस समय मोदी ने इसे तत्कालीन यू पी ए सरकार की आर्थिक नाकामी करार दिया था। परन्तु आज तो 1 डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 90 के करीब पहुँच चुकी है। आज देश की संसद में इसपर चर्चा क्यों नहीं होती ? दरअसल मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत देश का साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने में झोंक रखी है। खासकर चुनावों के समय ऐसी कोशिशों में और भी तेजी आ जाती है। बड़ा आश्चर्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राष्ट्रगान तक का विरोध करने वाले,गांधी की हत्या पर जश्न मनाने व मिठाइयां बांटने वाले,भारतीय संविधान को न पचा पाने वाले लोग आज सत्ता में आने के बाद बड़े ही शातिर तरीके से स्वयं को महान देशभक्त व धर्म के श्अभिरक्षक श बनने की कोशिश कर रहे हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

महिला ने घायल-बेसहारा जानवरों की सेवा के लिए नौकरी छोड़ी

भुवनेश्वर ११/१२ (संवाददाता): ऐसी दुनिया में जहाँ छोड़े हुए और बीमार जानवरों को अक्सर सड़कों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, ओडिशा की एक महिला ने आराम के बजाय दया को चुना है। पूरबी पात्रा, एक बहुत पढ़ी-लिखी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर अपनी ज़िंदगी घायल, छोड़े हुए और बूढ़े जानवरों को बचाने, उन्हें रहने की जगह, इलाज और सबसे बढ़कर, इज़्ज़त देने में लगा दी। भारतीय संस्कृति के 'जीबे दया' (सभी जीवों के प्रति दया) के सिद्धांत से प्रेरित होकर, पूरबी अनगिनत कुत्तों, गायों, बिल्लियों और पक्षियों के लिए जीवन रेखा बन गई हैं, जो वरना बिना देखभाल के मर जाते। चाहे सड़क किनारे पड़ा कोई एक्सीडेंट का शिकार जानवर हो या मालिक द्वारा छोड़ा गया कोई बूढ़ा पालतू जानवर, पूरबी बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए आगे आती हैं।

उन जानवरों के लिए एक जगह जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज़ करता है! कटक जिले के कांटापारा ब्लॉक के पिंगापाड़ा गाँव में उनका एनिमल केयर शेल्टर, जिसे कम संसाधनों और बहुत प्यार से बनाया गया है, उन जानवरों के लिए एक जगह बन गया है जिन्हें समाज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देता है। यहां जानवरों को खाना, मेडिकल केयर और इमोशनल आराम मिलता है, कई जानवरों को तो यह ज़िंदगी में पहली बार मिलता है। पूरबी के सफ़र को खास बनाने वाली बात उनका चुना हुआ फ़ैसला है। अच्छी क्वालिफ़ाइड होने और अच्छी नौकरी होने के बावजूद, उन्हें लगा कि उनका असली मकसद कहीं और है। सड़कों पर बार-बार दुखी जानवरों को देखकर वह कॉर्पोरेट लाइफ़ से दूर हो गईं और फुल-टाइम एनिमल रेस्क्यू में लग गईं। पूरबी ने कहा, आप यहां अलग-अलग नस्लों के कुत्ते देख सकते हैं। वे यहां अलग-अलग, भयानक हालात में आए थे। किसी को छोड़ दिया गया था, किसी को मैंने चंदाका सैंक्चुअरी से बचाया था, और किसी को बस बीच सड़क पर छोड़ दिया गया था। हम यहां बचाए गए सभी जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। पूरबी के लिए पैसे की तंगी, मैनपावर की कमी चुनौतियां पूरबी कहती हैं कि वह अपना दिन मुसीबत में फंसे जानवरों को बुलाने, घायल जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाने और उनकी देखभाल करके उन्हें ठीक करने में बिताती हैं। पैसे की तंगी और मैनपावर की कमी लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन उनका इरादा कभी नहीं डगमगाया। उनका मानना है कि हर जानवर दया का हक़दार है, और बचाव का हर काम इंसानियत का काम है।

बुरी तरह घायल स्ट्रीट डॉग्स को अपनी गाड़ी में उठाने से लेकर, छोड़ी हुई, बूढ़ी गायों को फिर से चलने में मदद करने तक, पूरबी का काम ओडिशा की सांस्कृतिक शिक्षाओं के गहरे मूल्यों को दिखाता है। उनकी कोशिशें समाज को याद दिलाती हैं कि दया कोई अमूर्त विचार नहीं है, यह एक ज़िम्मेदारी है। पूरबी पात्रा का मिशन पूरी तरह से हमदर्दी से चलता है। और ऐसे समय में जब कई जानवरों को बोझ समझकर छोड़ दिया जाता है, उन लोगों के प्रति उनकी सेवा जो अपने लिए बोल नहीं सकते, इस बात का सबूत है कि एक इंसान अटूट प्यार और हिम्मत से ज़्या हासिल कर सकता है।

आरएसपी में 33 केवी आउटडोर वीसीबी की आंतरिक रेट्रोफिटिंग से सिस्टम की विश्वसनीयता बहाल हुई

राउरकेला ११/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के नगर अभियांत्रिकी (विद्युत) के 33 केवी सबस्टेशन में 33 केवी/11 केवी, 6 एमवीए पावर ट्रांसफ़ार्मर 5 के दोषपूर्ण 33 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) के आंतरिक निराकरण और रेट्रोफिटिंग के साथ एक प्रमुख रखरखाव गतिविधि सफलतापूर्वक की गई थी। सीमेंस मेक का मौजूदा ब्रेकर बारह वर्षों से अधिक समय से सेवा में था और 10 नवंबर 2025 को पूरी तरह से निष्क्रिय होने से पहले लगातार परिचालन मुद्दों का सामना कर रहा था। विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और सिस्टम स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, खराब वीसीबी को एक इन-हाउस रेट्रोफिटिंग पहल के माध्यम से समान रेटिंग की एक अतिरिक्त इकाई के साथ बदल दिया गया था। 33 केवी सबस्टेशन, नगर अभियांत्रिकी (विद्युत) की एक समर्पित टीम ने पूरे काम को अंजाम दिया - जिसमें विघटित करना, रेट्रोफिटिंग, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल हैं। बिजली वितरण विभाग ने सिस्टम में ब्रेकर के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण समर्थन दिया। परियोजना टीम जिसमें शामिल हैं सहायक महाप्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी - विद्युत), श्री सी खेस, सहायक प्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी - विद्युत), श्री चित्रसेन जेना और अन्य सहायक कर्मचारियों ने इस कार्यभार के सफल निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए रेट्रोफिट किए गए वीसीबी को औपचारिक रूप से 28 नवंबर 2025 को मुख्य महाप्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी और बागवानी), श्री बी.के.जोजो द्वारा 33 केवी/11 केवी सिस्टम में औपचारिक रूप से शामिल किया गया।

इस मौके पर महाप्रबंधक (नगर अभियंत्रिकी - विद्युत और अनुभाग प्रमुख), श्री एम ए सिद्दीकी, महाप्रबंधक (नगर अभियंत्रिकी - विद्युत), श्री संजय प्रधान, महाप्रबंधक (नगर अभियांत्रिकी - विद्युत), श्री एस. सी. नायक और 33 केवी सबस्टेशन के कर्मचारी मौजूद थे। इस आंतरिक पहल ने न केवल टाउनशिप में बिजली वितरण की विश्वसनीयता में वृद्धि की, बल्कि संयंत्र के लिए लगभग 2.50 लाख रुपये की लागत की बचत भी हुई।

बरगढ़ में धान मंडियों को लेकर किसान-पुलिस संघर्ष, नेशनल हाईवे-53 पर यातायात ठप

बरगढ़ ११/१२ (संवाददाता): बरगढ़ ज़िले के गुड़भागा इलाके में तब तनाव की स्थिति बन गई जब नेशनल हाईवे -53 पर किसान और पुलिस आमने-सामने आ गए। सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे पर ही धान फैलाकर और सुखाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि मंडी के ठीक से काम न करने की वजह से वे मुश्किल में पड़ गए हैं। गुस्साए किसानों ने गुड़भागा में नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ भारी ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद यह जाम लगा। जब पुलिस ने रास्ता खाली कराने की कोशिश की, तो टकराव और बढ़ गया, जबकि किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया। बरगढ़ के सब-कलेक्टर प्रसन्न कुमार पांडे और स्थानीय SDPO समेत बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की।

इस रुकावट की वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। किसान दो घंटे से ज़्यादा समय से विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट लिखे जाने तक आंदोलन जारी था। बरगढ़ और संबलपुर दोनों तरफ सड़क पर पांच से सात किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं।

कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा खरीद की जगहें खुलने के बाद पिछले पांच-छह दिनों से धान मंडियों में यह रुकावट जारी है। हमें टोकन नहीं दिए गए हैं, और हमारी फसल अभी भी खुले में पड़ी है। हमें पक्का नहीं पता कि खरीद कब शुरू होगी। बरगढ़ सब-कलेक्टर ने आईएएनएस से कहा, इस बार लिफ्टिंग प्रोसेस बहुत धीमी है। हर साल इस समय तक आमतौर पर लगभग 40 परसेंट धान की खरीद हो जाती है। हालांकि, खरीद में अलग-अलग दिक्कतों की वजह से प्रोसेस धीमा हो गया है। पिछले सालों में टोकन हम तक एक ही समय पर पहुंचते थे। लेकिन इस साल, टोकन हमें फेज में भेजे जा रहे हैं।

चिल्का में मछली पकड़ने के जाल में फंसे 12 फुट के अजगर को बचाया गया

चिलिका ११/१२ (संवाददाता): ओडिशा की चिलिका झील में मछली पकड़ने के रूटीन काम के दौरान सोमवार को एक 12 फुट लंबे अजगर को बचाया गया। यह घटना बालूगांव के पास लक्ष्बोधरपुर गांव के पास हुई, जहां स्थानीय मछुआरों ने सुबह-सुबह अपने जाल में एक बड़े सांप को फंसा हुआ देखा। मछुआरों के अनुसार, अजगर का वज़न लगभग 40-50 किलोग्राम था। अचानक मिले इस अजगर से चौंककर, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बताया। अधिकारियों के मौके पर पहुंचने तक अजगर जाल में फंसा रहा। सूचना मिलने पर, चिलिका वाइल्डलाइफ डिवीजन की एक टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम को लीड कर रही वाइल्डलाइफ रेंजर रश्मिता जेना ने कन्फर्म किया कि अजगर मछली पकड़ने के जाल से सुरक्षित रूप से अलग हो गया था। अधिकारियों ने कहा कि रेस्क्यू के बाद अजगर की हालत स्थिर पाई गई। सफल ऑपरेशन के बाद, अजगर को पास की काली जुगेश्वर पहाड़ियों पर ले जाया गया और जंगल में छोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सांप की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसके जीवित रहने के लिए सही प्राकृतिक रहने की जगह देने के लिए इस इलाके को चुना गया था।

तनाव के बीच मलकानगिरी में इंटरनेट बंद 18 घंटे के लिए बढ़ाया गया

मलकानगिरी ११/१२ (संवाददाता): मलकानगिरी में, खासकर MV-26 और रखेलगुडा गांवों में मौजूदा तनाव को देखते हुए, जिले में इंटरनेट सर्विस का सस्पेंशन 18 घंटे और बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक, एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगलवार को एक ऑर्डर जारी किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बुधवार दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में विस्तार लागू किया गया है।

गृह अधिसूचना संख्या 50052/CP&M, दिनांक 08.12.2025 के क्रम में और कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, मलकानगिरी के अनुरोध के अनुसार उनके पत्र संख्या 261/Res. दिनांक 9.12.2025 के अनुसार, मैं, श्री सत्यब्रत साहू, ह्डस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सरकार, गृह विभाग इसके द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ङ्ग जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट और डेटा सेवाओं के अन्य माध्यमों के उपयोग और पहुंच पर प्रतिबंध को दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 और शेष सभी शर्तों के साथ मलकानगिरी जिले में 10.12.2025 को दोपहर 12ः00 बजे तक और 18 घंटे के लिए बढ़ाता हूं। नोटिफिकेशन में आगे लिखा है, यह ऑर्डर सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट बेस्ड सर्विस, जैसे ह्स्ब्बह (ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क), ह्ड्ढष्ट नेट, ह्यह (नेशनल नॉलेज नेटवर्क), बैंकिंग, रेलवे या किसी दूसरी सरकारी सर्विस पर लागू नहीं होगा। ऑर्डर का उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि मलकानगिरी जिले में तनाव बना हुआ है क्योंकि एक महिला की बिना सिर वाली लाश मिलने के बाद रुङ्क-26 और रखेलगुडा गांवों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। इस घटना से जिले में आगजनी और अशांति फैल गई है।

आईजीएच ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए जटिल वृद्धावस्था शैल्याचिकित्सा की

राउरकेला ११/१२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट चिकित्सकीय क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए पूर्व कर्मचारी की पत्नी, 91 वर्ष 10 माह की वृद्ध महिला का सफल उपचार किया और सिद्ध कर दिया कि उम्र शल्य- चिकित्सा में बाधा नहीं बन सकती । रोगी को अत्यंत गंभीर स्थिति में भर्ती किया गया था। वह मस्तिष्क रक्तस्राव, खराब सामान्य स्वास्थ्य, प्रतिक्रिया में कमी, बोलने और खाने में असमर्थता तथा दाहिनी तरफ पक्षघात (हेमिपेरेसिस) से ग्रसित थीं।

गहन जाँच और परिजनों की सहमति के बाद, चिकित्सा टीम ने जीवनरक्षक शल्य हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। रोगी की लघु क्रैनियोटॉमी कर रक्तस्रावित हेमाटोमा को निकाला गया। यह शल्यचिकित्सा वरिष्ठ कंसल्टेंट (न्यूरोसर्जन), डॉ. मनोज कुमार देव द्वारा की गई। शल्यचिकित्सा के दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थीसिया), डॉ- संजुक्ता पाणिग्रही ने एनेस्थीसिया सहायता प्रदान किया, जबकि ब्रदर कमलाकर और सिस्टर अर्चना ने शल्यचिकित्सा के दौरान आवश्यक सहायता दी।

शल्यचिकित्सा के बाद रोगी को आईसीयु में स्थानांतरित किया गया, जहाँ उन्हें नियंत्रित रूप से वेंटिलेशन पर रखा गया और धीरे-धीरे वेंटिलेटर से हटाया गया। लगभग एक महीने तक उन्हें शल्य चिकित्सा के पश्चात गहन सेवा मिली। उनकी स्थिति लगातार सुधरती गई, वे होश में आई, शब्दों और अधूरे वाक्यों का उच्चारण शुरू किया तथा सीमित रूप से भोजन ग्रहण करना भी प्रारंभ किया। आईसीयु में उनकी देखभाल सिस्टर शाइनी जॉर्ज और अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा की गई, जबकि वार्ड में आगे की देखभाल सिस्टर पद्मावती, सिस्टर जानकी, सिस्टर रीमा और उनकी टीम द्वारा सुनिश्चित की गई। मरीज की निरंतर स्वास्थ्य लाभ समन्वित बहु-विषयक चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता को दर्शाता है ।

इस मामले का सफल प्रबंधन जटिल वृद्धावस्था शल्यचिकित्सा में उत्कृष्टता के लिए आईजीएच की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है, जो अपने सभी हितधारकों के लिए उन्नत, रोगी-केंद्रित और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा मानकों को बनाए रखने के लिए सेल, आरएसपी की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।